जिला	वन आवरण 1991 मूल्याकंन	वन आवरण - 1993 मूल्याकंन
सरगुजा	12,106	12,106
टीकमगढ़	263	263
उज्जैन	-	-
विदिशा	970	970
	135,785	135,396

Steps to intensify patrolling in the International Borders

197. SHRI ISH DUTT YADAV: SHRI SANJAY DALMIA: MAULANA OBAIDULLAH KHAN AZMI:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state the steps taken and proposed to be taken by Government to intensify patrolling in the international borders where fencing is not possible?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SYED SIBTEY RAZI): Steps taken to intensify patrolling in the border areas include the erection of OP Towers, increase in the number of Nakas, supply of sophisticated gadgets, including night vision division, jeeps, tractors, motor cycles and motor boats as well as the reduction of gaps between BOPs in vulnerable areas.

Chinese Nuclear Sales to Pakistan

198. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government are aware of Pakistan's recent involvement with China,, to develop its nuclear weapons programme in addition to illegal M-ll missile transfer from China to Pakistan;

(b) whether Government's attention has also been drawn to a newsitcm published in the Hindustan Times dated 11th February, 1996 captioned. "Pak fails to allay US concerns" and reported CIA's disclosure of China's selling 5,000 ring magnets used in equipment that enriches uranium for weapons, to Pakistan; and

(c) if so, whether Government have any plan to exercise its nuclear option to meet the country's security challenges?

THE MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI PRANAB MUKHERJEE): (a) and (b) Yes, Sir. Government have seen media reports on transfer of equipment for use in uranium enrichment plant from China to Pakistan.

(c) Government are fully aware of the clandestine nature of Pakistan's nuclear weapons programme. The security situation of India is constantly under review particularly in the light of developments in the neighbourhood. Government will take all necessary measures designed to cope with any threat that may be posed to the security of the nation.

हिसार मे उपमार्ग (बाईपास) निर्माण

199.**श्री राम जी लाल :** क्या जल भूतल परिवाहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात जानकारी है कि हिसार (हरियाणा) से पीलीबंगा (राजस्थान) तक की सीमा सड़क सगंठन की सड़क (बी. आर. ओ. रोड) हिसार शहर से होकर गुजराती है और इस कारण इस सड़क पर कई दुर्घटनायें होती रहती हैं जिनमें जान-माल का नुकसान हो रहा है;

(ख) क्या सरकार दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से इस सड़क पर हिसार शहर के दक्षिणी छोर पर एक उप-मार्ग का निर्माण करवायेगी.

(ग) यदि हां , तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक कराये जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

जल भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम . राजशेखर मूर्ति): (क) से (घ)

हिसार –पीलाबंगी सड़क पर कुछ दुघर्टनाओं की सूचना मिली हैं । निधियों के अभाव के कारण हिसार शहर के दक्षिणी छोर पर बाईपास का निर्माण कार्य शुरू करना संभव नहीं हो पाया हैं।

खाद्य प्रसंस्करण संबंधी विदेशी उद्यमों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापना किया जाना

200.**श्री नारामणि** :

चौधरी हरमोहन सिहं:

(क) क्या यह सच है कि सरकार खाद्य प्रसंस्करण संबंधी विदेशी उद्यमों को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित करने में असफल रही है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) गत दो वर्षो के दौरान राज्य-वार किन – किन विदेशी खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को अनुमति दी गई हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री के,. पी . सिंह देव): (क) और (ख) जी नहीं । उदारीकरण के बाद अर्थात् जुलाई 1991 से दिसम्बर, 1995 तक खाद्य प्रसंस्करण के विभित्र क्षेत्रों में यूनिटों स्थापित करने के लिए अनुमोदित 3394 करोड़ रू के कल विदेशी और अनिवासी भारतीय इक्विटी निवेश में से लगभग 3000 करोड़ रू का विदेशी और अनिवासी भारतीय इक्विटी निवेश गैर – शहरी तथा ग्रामीण इलाकों में स्थपित किए जाने वाले उद्यमों के लिए हैं।

(घ) हालांकि 1994-95 और 1995-96 के दौरान बड़ी संख्या मे विदेशी निवेश प्रस्तावों को मजूरी दी गई हैं, प्रत्यक्षतःया सयुक्त उद्यम में निवेश के लिए मंजूरी प्राप्त कुछ प्रमुख विदेशी खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों की सूची विवरण के रूप में संलग्न हैं।

विवरण

कुछ प्रमुख विदेशी कपंनियों के ब्यौरे जिनके खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संबंधी प्रस्तावों को 1994-95 तथा 1995-96 के दौरान मंजूरी दी गई हैं।

क्रम सं	विदेशी कंपनी का नाम	राज्य जिसमें प्रस्तावित यूनिट स्थपित की जानी हैं
1	पिल्सबरी कं. अमरीका	महाराष्ट्र
	मक्केन फूड्स लि, कनाडा	उत्तर प्रदेश / पंजाब
3	सीग्राम कं लि. कनाडा	उत्तर प्रदेश
4	देरा एग्रो टेक्रोलॉजिज ,इस्त्रायल	तमिलनाडु
5	वर्नप्रिलिप एंड कं. आस्ट्रेलिया	प्र बंगाल
6	चुपाचुप कनफैक्शनरी , हॉलैड	तमिलनाडु
7	ग्रुप डैनोन, फ्रांस	स्थान का उल्लेख नहीं है
8	व्हाइट एंड मैंके , यू.के.	उत्तर प्रदेश
9	पर्नोड रिकार्ड यू0 के	महाराष्ट्र
10	ब्राउन फोर्मेन यू.के	पंजाब
11	थाइसेन राइनस्टॉल टेक्रालाजी जर्मनी	महाराष्ट्र
12	सी .पी.सी इन्टरनेशनल , अमरीका	महाराष्ट्र
13	डोलहर जी एम बी एच जर्मनी	तमिलनाडु
14	फार्म फ्राइटस वी.वी हालैंड	पं. बंगाल
15	डल्सेम वैसिऐप बी.वी हालैंड	राजस्थान, आन्ध्र प्रदेश मध्य प्रदेश
16	फ्रैकलिन मशरूम इंक. अमरीका	पं.बंगाल आंध्र प्रदेश
17	सेफ्टी हैन्डल्स जीएम बी.एच जर्मनी	केरल, पं.बंगाल, आंध्र प्रदेश
18	एग्री सिस्टम बी.वी हालैड	आध्र प्रदेश
19	मेकन एग्री लि. उत्तरी आयरलैंड	हरियाणा. राजस्थान , गुजरात ,मध्य प्रदेश .
20	जर्लिन होल्डिंग्स,. हॉलैड	महाराष्ट्र